INDIAN COUNCIL OF WORLD AFFAIRS

POLICY BRIEF

भारत और अमरीका: स्थिरता की ओर अग्रसर

*डॉ. स्तुति बनर्जी**

आज के उभरते भू-राजनैतिक परिदृश्य में, सर्वाधिक आबादी वाले लोकतंत्र भारत और सबसे प्राचीन लोकतंत्र अमरीका के बीच के संबंध को अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता के प्रसार के प्रमुख अंग के रूप में देखा जाता है। सोवियत संघ के पतन के बाद भू-राजनैतिक परिवर्तनों ने भारत और अमरीका के बीच नई सहयोगात्मक पहल के राजनैतिक द्वार खोल दिए हैं। इन परिवर्तनों के संकेत के रूप में, दोनों देश वर्ष 2004 के बाद से ही एक ऐसी "कार्यनीतिक भागीदारी" को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें अनेक आर्थिक, सुरक्षा और वैश्विक पहल समाहित हैं। अपनी 'एशिया की धुरी' विदेश नीति के भाग के रूप में, अमरीका भारतीय अर्थव्यवस्था और रक्षाबलों की बढ़ती क्षमताओं की ओर ध्यान दे रहा है।

अमरीका भारत के साथ सुरक्षा सहयोग को सामान्य सिद्धांतों और साझा राष्ट्रीय हितों के साथ-साथ कार्यनीतिक उद्देश्यों जैसेकि आतंकवाद को मात देने, हथियारों का प्रसार रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता कायम रखने के संदर्भ में देखता है।[i] अमरीका प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व वाली प्रथम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के साथ रहे अपने अच्छे संबंधों को आगे बढ़ाना चाहता है। उस दौरान भारत और अमरीका ने संबंधों की जो नींव रखी थी वह आज भी फल-फूल रही है। द्वितीय एनडीए सरकार के कार्यभार संभालने के पहले 100 दिनों के भीतर ही विदेश मंत्री जॉन केरी, वाणिज्य मंत्री पेनी प्रिट्ज़ेकर और रक्षा मंत्री चक हेगेल के भारत आने का शायद यही मुख्य कारण था। यह संबंधों को "*पुन: ऊर्जावान बनाने*" और "---- सही मायनों में भारत-अमरीका कार्यनीतिक भागीदारी सृजित करने की वाशिंगटन की इच्छा का संकेतक है ---- (जो) ---- दक्षिण एशियाई क्षेत्र, एशिया और विश्व भर में शांति, स्थिरता और संपन्नता लाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।[ii] अमरीकी विदेश विभाग और रक्षा विभाग दोनों ही के अधिकारीगण इस बात से सहमत हैं कि भारत की "पुर्वोन्मुख नीति" और अमरीका की "एशिया-प्रशान्त पुनर्संतुलन नीति" का स्वाभाविक उद्देश्य एक है।[iii]

भारत में नई सरकार आने के साथ ही दोनों देशों में नए सिरे से आशा जगी है कि ये संबंध परमाणु सौदे के बाद से ही अनुभव किए जा रहे खालीपन को भरने में सक्षम होंगे। यह आशा भारत सरकार द्वारा अपने सुरक्षा हितों और आर्थिक विकास के संवर्धन हेतु (अन्य) राष्ट्रों के साथ भारत के संबंध सुदृढ़ करने पर दिए गए जोर के कारण उपजी है। अमरीका इस क्षेत्र में भारत द्वारा अर्जित सद्भावना से वाकिफ है और वह स्वयं को स्थिर करने में सहयोग के रूप में भारत के संबंधों का लाभ उठाना चाहता है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि दक्षिण एशिया कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा के स्पष्ट उत्थान, चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति और तुलनात्मक रूप से अमरीका के घटते प्रभाव का साक्षी बन रहा है।

एक जिम्मेदार, प्रभावशाली विश्वशक्ति के रूप में भारत के उत्थान को मूर्त रूप देने में अपने प्रमुख सहयोगी अमरीका के साथ अपनी भागीदारी को जैसी प्राथमिकता भारत देता है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली-पहल अमरीका यात्रा के दौरान जोर दिया। राष्ट्रपति ओबामा ने स्वीकार किया कि एक मित्र और सहयोगी के रूप में भारत का उत्थान अमरीका के हित में है। उन्होंने (दोनों नेताओं ने) वैश्विक स्थिरता लाने और आगामी 10 वर्षों में लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में सुदृढ़ तथा प्रगाढ़ सहयोग के मार्गदर्शक के रूप में प्रथम "कार्यनीतिक भागीदारी हेतु संकल्पना वक्तव्य" का समर्थन किया। उन्होंने भागीदारी के लिए एक नए मंत्र "*चलें साथ-साथ: FORWARD TOGETHER WE GO*"[iv] के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

“कार्यनीतिक भागीदारी” को परिभाषित करने में भागीदारी को पुन: ऊर्जावान बनाना और एक दृष्टिकोण कायम करना महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कतिपय संस्तुतियां सुझाई गई हैं।

(क) रक्षा तथा सुरक्षा संबंध:

भागीदारी का एक महत्वपूर्ण और संभवतः अग्रणी पहलु दोनों देशों द्वारा साझा किया गया सुरक्षा संबंध है। एशिया की सुरक्षा में इनके साझा हित नीहित हैं और यदि ये (दोनों देश) एक औपचारिक गठबंधन में न भी बंधें तो भी सुरक्षा संबंध इनके बीच भागीदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगा। रक्षा सहयोग सकारात्मक और परस्पर लाभप्रद दिशा में आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सेनाओं के आपसी सहयोग में विस्तार हुआ है, आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों में बढ़ोत्तरी हुई है और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर वार्ताओं में अत्यधिक प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के अंत में जारी संयुक्त वक्तव्य इस क्षेत्र में सहयोग में सुदृढ़ता को प्रमाणित करता है। घनिष्ठ रक्षा सहयोग को और सुविधाजनक बनाने के लिए भारत और अमरीका ने ‘अमरीका-भारत रक्षा संबंध फ्रेमवर्क-2005’ को अगले 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है और अपने रक्षा दलों को और अधिक महत्वकांक्षी कार्यक्रमों और कार्यकलापों के लिए योजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच परस्पर विश्वास का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ एक दूसरे के उपकरणों और सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच और अधिक संपर्क कायम करके गतिशीलता बनाए रखने की जरूरत है। भारत और अमरीका ने रेड फ्लैग कार्रवाइयों/अभ्यासों में मिलकर भागीदारी की है लेकिन ये नियमित सहभागिता के रूप में विकसित नहीं हुए हैं। इस सहयोग को उन्नत रक्षा व्यापार से अनुपूरित किए जाने की भी जरूरत पड़ेगी। इस पहलु में नौकरशाही अड़चनें दोनों देशों की समान चिन्ता है और दोनों ही सरकारों द्वारा इसका समाधान किए जाने की जरूरत है। भारत को और अधिक रक्षा प्रौद्योगिकी तथा सामानों का निर्यात करने के लिए अमरीका को अपने निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में अभी और सुधार करना चाहिए। अमरीका ने कुछ भारतीय सामग्रियों को प्रवेश सूची से हटा तो दिया है लेकिन प्रौद्योगिकी निर्यात के मामलों में यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी साझा करने से अभी भी झिझक रहा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये संबंध एक खरीददार और विक्रेता के हैं। इसके जवाब में भारत इस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ा सकता है। तथापि, भारत को रक्षा उत्पादन में अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए स्वयं ही कदम उठाना जारी रखना होगा।

आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए खुफिया जानकारी साझा करना इस संबंध का एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जलदस्युता के खतरे से सुरक्षा के लिए दोनों नौसेनाओं की पेट्रॉलिंग के बीच बृहत्तर सहयोग भी हैं। नौसैनिक संयुक्त अभियान, मालाबार नौसैनिक अभ्यास सहित, सभी सहयोगों में सर्वाधिक सफल रहे हैं।

(ख) आर्थिक संबंध:

आर्थिक क्षेत्र में संबंध पिछले कुछेक वर्षों में विकसित हुए हैं और व्यापार बढ़कर लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर हो गया है। लेकिन वर्ष 2020 तक प्रत्याशित 500 अरब अमरीकी डॉलर की पूर्ण क्षमता तक इसका पहुंचना अभी बाकी है। भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढ़ांचे का विकास, कृषि उत्पादन, विमान उद्योग और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा, जो अमरीका के लिए लंबे समय से चला आ रहा विवादास्पद मुद्दा रहा है, जैसे क्षेत्रों में हो सकते हैं। एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों के लिए कम लागत वाली जीवन रक्षक औषधियां विकसित किए जाने की आवश्यकता जेनेरिक बनाम ब्रांड नामों वाली औषधियों के बीच वाद-विवाद का हिस्सा है।

भारत और अमरीका को और अधिक बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियां विकसित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, जिससे न केवल द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ेंगे बल्कि इस क्षेत्र के अन्य राष्ट्र भी इसमें शामिल हो सकेंगे। यदि राष्ट्र एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं में निवेश करते हैं तो वे संभवत: शांति व स्थिरता को भी बढ़ावा दे सकेंगे। इससे सामानों के बिना रूकावट प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य देशों के साथ संपर्क विकसित करने में सहायता मिलेगी। दोनों देशों को, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और जी-20 के सदस्य के रूप में, अपने-अपने क्षेत्र में सीमाओं के पार उत्पादों के अबाध व उपयुक्त नियंत्रित प्रवाह को प्रोत्साहित करने के लिए काम करना चाहिए। भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) में भी शामिल हो जाएगा और यह प्रशान्त-पार भागीदारी (टीपीपी) के तहत विकल्पों की तलाश कर रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था में जैसे-जैसे भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, यह विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसे मंचों पर अपनी स्थिति बयां करने की बेहतर स्थिति में होगा। इसे (भारत को) इस स्थिति का उपयोग विकासशील दुनियां की चुनौतियों को सामने लाने में करना होगा। इसे अमरीका सहित विकसित राष्ट्रों को मनाना होगा कि वे कृषि सब्सिडी तथा अन्य प्रशुल्क कम करें और साथ ही साथ इसे अपने कृषि क्षेत्र में भी इसी प्रकार की छूट प्रदान करनी होगी।

अमरीकी वैज्ञानिकों ने भारत को पहली 'हरित क्रांति' प्रारंभ करने में सहायता दी थी, जिसने 1960 की दशक में कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। आज जब भारत ऐसी दूसरी क्रांति की आवश्यकता पर चर्चा कर रहा है तो भारत और अमरीका को पुन: मिलकर काम करना होगा।

अमरीकी सरकार ने अजमेर (राजस्थान), विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश) और इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) को स्मार्ट सीटी के रूप में विकसित करने में अग्रणी भागीदार के रूप में अमरीकी उद्योग जगत को दिए गए भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री वर्ष 2015 में दो व्यापार आयोगों का स्वागत करेंगे जिनका उद्देश्य अमरीकी प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं से भारत की बुनियादी ढ़ांचे से जुड़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा।

ग) परमाणु मुद्दे

असैनिक परमाणु करार संबंधों की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम था और इसे दोनों देशों के एक-दूसरे पर विश्वास के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस करार की क्षमताओं को प्राप्त करने की विफलता ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) और अन्य परमाणु पर्यवेक्षक व्यवस्थाओं से भारत को

छूट की आवश्यकता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। भारतीय परमाणु उत्तरदायित्व कानून को अमरीकी फर्मों से बोलियां प्राप्त न होने के प्रमुख कारण के रूप में देखा गया है। भारत को दो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इस मुद्दे पर चर्चा हेतु कदम उठाना चाहिए, पहला अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना और दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि यह सौदा पूरी तरह से हो भी जाए।

अमरीका की व्यापार नियंत्रण व्यवस्था भारत के लिए चिंता का विषय रही है। अमरीका को संवेदनशील प्रौद्योगिकी के प्रसार का डर है, फिर भी इसने अपने कानूनों के साथ संगति वाले कुछ नियंत्रणों को हटा लिया है। दोनों देशों को धैर्य बनाए रखना है और इस दिशा में छोटे उपाय करने हैं। प्रौद्योगिकी के दोहरे उपयोग तक पहुंच/प्रवेश को सीमित करना दोनों ही देशों की न्यायसंगत चिंता है। ऐसा करने से परमाणु व्यापार, अप्रसार तथा परमाणु नि:शस्त्रीकरण के क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी।

परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन प्रक्रिया के सक्रिय भागीदारों के रूप में अमरीका और भारत ने आतंकवादियों द्वारा परमाणु हथियारों अथवा इससे संबंधित सामग्रियां प्राप्त कर लेने के खतरे को कम करने की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया और राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तरों पर परमाणु सुरक्षा बढ़ाने के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता का संज्ञान लिया। अमरीका ने भारत को वैश्विक अप्रसार व्यवस्थाओं की मुख्य धारा में शामिल कर लिया है लेकिन इसे भारत से परमाणु अप्रसार संधि (एमटीपी) का पक्षकार बनने के लिए अब नहीं कहना चाहिए। भारत को भी अपनी ओर से परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए अमरीका तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करनी चाहिए। भारत को 'राजीव गांधी परमाणु नि:शस्त्रीकरण कार्ययोजना' में संशोधन करके इसके संशोधित स्वरूप का प्रस्ताव करना चाहिए।

(घ) राजनैतिक संबंध

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने कहा था कि विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमरीका '*स्वाभाविक सहयोगी*' हैं। इन दोनों देशों की एकसमान अंतर्निहित राजनीतिक विशेषता, लोकतंत्र ही इनके संबंधों की नींव है। फिर भी, लोकतंत्र की अवधारणा और मानवाधिकारों की संकल्पना के प्रति इनके दृष्टिकोणों में अंतर है। इन भिन्न दृष्टिकोणों के कारण अतीत में असहमतियां पैदा हुई हैं और भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। दोनों राष्ट्रों को यह स्वीकार करना होगा कि कभी-कभार मतभेद पैदा होंगे और इनपर चर्चा की जानी चाहिए। तथापि, इन मतभेदों के कारण बृहत्तर भागीदारी को रूकने नहीं

दिया जाना चाहिए। इनकी भागीदारी में वह क्षमता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश तथा श्रीलंका सहित दक्षिण एशिया में और अधिक स्थिरता, सुरक्षा व आर्थिक सम्पन्नता ला सके।

क्षेत्रीय मुद्दों पर होने वाली वार्ताओं में पाकिस्तान और चीन के साथ इनके (भारत और अमरीका के) अपने-अपने द्विपक्षीय संबंधों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इन दोनों देशों के प्रति भारत और अमरीका दोनों के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न हैं। यह महत्वपूर्ण है कि भारत और अमरीका दोनों इसे समझें और अन्य एशियाई राष्ट्रों के साथ साझा किए जाने वाले संबंधों में दोनों ही एक दूसरे के हित और प्रकृति के प्रति सजग रहें। अफगानिस्तान के संबंध में अमरीका को आगे और विकास योगदान प्राप्त करने के साथ-साथ अभी तक अस्थिर इस देश पर एक स्थिर लोकतांत्रिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए भारत को साथ लेना होगा। भारत को अपनी सुरक्षा के लिए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अमरीका उन मामलों में इसकी अनदेखी न कर पाए जो इसके पड़ोस से संबंधित हों। इसे इस क्षेत्र के राजनैतिक और आर्थिक परिदृश्य में और ज्यादा सक्रिय बनना होगा।

भारत और अमरीका के बीच संबंध इनके परस्पर हितों से प्रेरित हैं, विशेषकर एशिया में। इस संबंध ने कुछ परिणाम दिखलाए तो हैं लेकिन इसे अभी और पोषित करने की जरूरत है।

**डॉ.स्तुति बनर्जी विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्येता हैं।*

समाप्ति नोट

---

[i] के. एलन क्रोन्स्ताद्त और सोनिया पिंटो, “अमरीका-भारत सुरक्षा संबंध : कार्यनीतिक मुद्दे”, कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस, वाशिंगटन डीसी, 2013, पृ.01

[ii] अमरीकी विदेश विभाग, “पांचवीं भारत-अमरीकी कार्यनीतिक वार्ता पर संयुक्त वक्तव्य”, 12 सितंबर, 2014 को एक्सेस किया गया, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/07/230046.ht m

[iii] एनडीटीवी, “सुदृढ़ भारत विश्व शांति के लिए लाभदायक: अमरीका”, 12 सितंबर 2014 को एक्सेस किया गया, http://www.ndtv.com/article/ india/stronger-india-is-beneficial-for-world-peace-us-585519

[iv] प्रेस सचिव, द व्हाइट हाउस का कार्यालय, "अमेरिका-भारत संयुक्त वक्तव्य", 01 अक्तूबर 2014 को एक्सेस किया गया, http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/30/us -India-joint-statement